नए संसद भवन की आधारशिला

-लेखकः अरुण मायरा (पूर्व सदस्य, योजना आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

12 दिसम्बर, 2020

यदि सभी स्वास्थ्य और समृद्धि तक पहुंच रखने में कामयाब रहते हैं तो एक नए संसद भवन का निर्णय उचित प्रतीत होगा।

भारत के लिए एक नए संसद भवन की नींव रखना एक उत्सव का अवसर होना चाहिए, हर एक नागरिक को संपन्न लोकतंत्र में रहने का गर्व होना चाहिए। फिर भी, समारोह अब मुकदमेबाजी की छाया में होने के लिए तैयार है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस आयोजन को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। विदित हो कि याचिकाएं भूमि उपयोग बदलाव की मंजूरी सहित दी गई अन्य विभिन्न मंजूरियों के खिलाफ दायर की गई हैं। ये सभी अभी शीर्ष अदालत में विचाराधीन हैं।

अब एडविन लुटियन तथा हरबर्ट बेकर के डिजाइन की संसद भवन की इमारत, जिसके निर्माण में हजारों भारतीय मजदूरों ने दिन-रात एक किया था, इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। 12 फरवरी, 1921 को ब्रिटेन के ड्यूक आफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी थी। यह छह सालों में 83 लाख रुपये के कुल खर्च में बनी थी। देश को जो नया संसद भवन मिलने जा रहा है, उसके निर्माण पर 971 करोड़ रुपये की लागत आएगी। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्गमीटर बड़ा होगा। इसे 64,500 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा।

नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहाँ सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। संसद के नए भवन में निचले सदन लोक सभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई इमारत में लोक सभा भूतल में होगी।

वहीं उच्च सदन राज्य सभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार की इच्छा है कि संसद की नई इमारत 2022 तक बन जाए, जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो। मगर इतने मेगा प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से भी किया जा सकता था।

कुछ हफ्ते पहले, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की कुल लागत की गणना नहीं की गई थी, लेकिन इस योजना के हजारों करोड़ों में शामिल होने का अनुमान है। यहाँ सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्या इन मौजूदा इमारतों में सुधार करके काम नहीं चलाया जा सकता था?

लेकिन सरकार अब अपने इस परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है वो भी तब जब देश धीमी अर्थव्यवस्था और COVID-19 महामारी के दोहरे प्रहार से कमजोर बना हुआ है। शायद सरकार यह मान रही है कि टीकाकरण के बाद के युग में अर्थव्यवस्था मजबूत हो कर उभरेगी और देश की दुर्बलता को आसानी से दूर कर देगी, लेकिन यह विचार उचित नहीं है। सरकार अब तक बड़े पैमाने पर निजी खपत और व्यवसायों के मामूली पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं, जबकि अपने स्वयं के उपभोग व्यय, वर्ष की पहली छमाही के दौरान तक, पिछले वर्ष की तुलना में नीचे रहा है।

इस प्रभाव ने अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले जीडीपी को बड़े संकुचन की ओर ले आया है। निशुल्क COVID-19 वैक्सीन के सवाल पर भी सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। संसाधनों के आवंटन पर चिंताओं के साथ, यह किसी मायने में उचित नहीं प्रतीत होता है कि नई सेंट्रल विस्टा परियोजना से स्वतंत्रता जयंती की चमक बढ़ जाएगी। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि केंद्र की पीडब्ल्यूडी, समग्र रूप से पुनर्विकास योजना को संशोधित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बदलाव को

प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा। इस अभूतपूर्व संकट के वर्ष में सबसे त्रस्त नागरिक है, जिन्हें अपने जीवन को स्थिर करने के लिए हर समय रुपये की आवश्यकता होती है।

अगर वे सरकार से यह पूछते है कि ये सौंदर्यीकरण उनके परिवार को सुदृढ़ करने के बाद क्यों नहीं किया जा सकता है, तो गलत नहीं होगा। महामारी ने हमारी सबसे कमजोर कड़ी को उजागर किया है वह है स्वास्थ्य देखभाल और सरकार को 75वीं वर्षगांठ पर नागरिकों को इसकी गारंटी देना चाहिए। अगर इसे सुनिश्चित किया जाता है तो फिर नई संसद का निर्माण हर एक नागरिक के लिए जश्न की बात हो सकती है।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी।
- नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। ये एक तिकोनी इमारत होगी जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्ताकार है।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' के तहत एक नए संसद भवन के निर्माण के अपने निर्णय को सही ठहराने के पक्ष में दलीलें पेश की गईं हैं।
- याचिकाकर्त्ताओं द्वारा नवीन संसद भवन के निर्माण के केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

क्यों बनाया जा रहा है नया संसद भवन?

- सरकार और अधिकारियों के अनुसार संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई।
- अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था जो लगभग 100 वर्ष (93 वर्ष) पुराना है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है।

कब तैयार हो जाएगी नई इमारत?

- लोकसभा सचिवालय के अनुसार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नया संसद भवन अक्तूबर 2022 तक बन जाएगा। काम दिसंबर 2020 में शुरू करने की उम्मीद जताई गई है।
- हालाँकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है।
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देती तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़-फोड़ का काम नहीं करेगी।

नया संसद भवन कितना बड़ा होगा?

- संसद के नए भवन में निचले सदन लोक सभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई इमारत में लोक सभा भूतल में होगी।
- वहीं उच्च सदन राज्य सभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे।
- ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है।
- भारत में अभी लोक सभा में 543 और राज्य सभा में 245 सीटें हैं।
- नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहाँ 1272 सदस्य बैठ सकेंगे।

इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा?

- अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएँ होंगी ताकि 'पेपरलेस दफ्तरों' के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके।
- नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा।
- साथ ही वहाँ सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी।
- इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा।
- अधिकारियों के मुताबिक संसद की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपये होगी।

दिल्ली की हुकूमत: अनंगपाल तोमर से लेकर नरेंद्र मोदी तक

- कई बार बनी और तबाह हुई दिल्ली का पहला प्रामाणिक इतिहास आठवीं शताब्दी से मिलता है। उस वक्त दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर का शासन था।
- अनंगपाल तोमर की सत्ता उनके बनाए गए लाल कोट किले से चलती थी। तमाम इतिहासकार इसी को वास्तविक लाल किला मानते हैं।
- इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और सल्तनत काल का एक लंबा दौर गुजरा, लेकिन दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र बनी रही।
- मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लाल किले का निर्माण कराया।
- 1857 के गदर में अंग्रेजों से हारने और बंदी बनाकर बर्मा भेजे जाने तक अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी लाल किले से अपनी सत्ता चलाते रहे।
- इसके बाद कुछ वक्त तक अंग्रेजी राज की राजधानी कोलकाता रही, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने अपनी घोषणा के साथ दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बना दिया।

- 1931 तक वायसरॉय और उनके सचिवालय के लिए नई बिल्डिंग्स बनाई गईं और देश के आजाद होने यानी 1947 तक अंग्रेजी हुकूमत इन्हीं बिल्डिंगों के जरिए चली।
- अब 2020 में केंद्र की मोदी सरकार इसी सेंट्रल विस्टा, संसद भवन और दूसरे केंद्रीय मंत्रालयों के दफ्तरों को फिर से डिवेलप कर इसे नया रूप देना चाहती है।
- भारत की हुकूमत अब इन्हीं नए संसद परिसर, सेंट्रल विस्टा और कॉमन सचिवालय से चला करेगी।

1931 में विकसित हुई थी मौजूदा लुटियंस दिल्ली

- रायसिना हिल्स पर मौजूद बिल्डिंग्स का निर्माण 1911 से 1931 के बीच हुआ था।
- इसका डिजाइन सर एडविन लुटियन और सर हरबर्ट बेकर ने बनाया था।
- उस वक्त इन बिल्डिंग्स को वायसरॉय और उनके सचिवालय के लिए तैयार किया गया था। इसी अवधि में संसद भवन भी बनाया गया था।
- राजपथ के इर्दगिर्द मौजूद कई बिल्डिंग्स को अलग-अलग चरणों में मंत्रालयों और विभागों की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता रहा।
- सेंट्रल विस्टा की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से होती है और यह इंडिया गेट तक जाता है।
- इस पूरे इलाके को डिवेलप हुए 100 साल गुजरने के बाद रायसिना हिल और राजपथ को फिर से तैयार करने की जरूरत सरकार को लग रही थी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. संसद के नए भवन में निचले सदन लोक सभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
2. वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' की परिकल्पना की गई थी।
3. वर्तमान संसद भवन का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 2 और 3
(c) 1 और 3 **(d)** उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Central Vista Project:-

1. The seating arrangement of 888 members of the lower house of Lok Sabha has been made in the new house of Parliament.
2. The 'Central Vista Redevelopment Project' was envisaged by the Ministry of Housing and Urban Affairs in the year 2019.
3. The present Parliament House was constructed in the year 1927.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 **(b)** 2 and 3
(c) 1 and 3 **(d)** All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की कमजोर स्थिति के बीच सरकार द्वारा नए संसद भवन की नींव कितनी प्रासंगिक प्रतीत होती है? चर्चा कीजिए।
(250 शब्द)

Q. What is the Central Vista Project of central government? How relevant does the foundation of the new Parliament House seem to be by the government amid the present weak state of the Indian economy and public health care? Discuss.
(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।